Your Imagination, we Print...
JGP
JAY graphics & printers
COMMERCIAL PRINTERS
C-15 VIKRAM CHAMBARS, NR.INCOME TAX OFFICE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD.
Ph. : 93288 95485

Regd.RNI.No. GUJHIN/2016/72566

GANDHINAGAR

पाटनगर उदय

प्रधान सम्पादक : ईलेवान एच. ठाकर
मो.नं. : 99784 07016

सह सम्पादक : सुरेश के. मालाणी
मो.नं. 97269 63888

• वर्ष : 10 • अंक : 303 • दिनांक :- 08-08-2026, SATURDAY • पेज 4+4 मुल्य: 0.90/- (Paisa) • वार्षिक शुल्क : 280/-

'पाटनगर उदय'
दैनिक समाचार पत्र में समाचार, प्रेस नोट एवं विज्ञापन के लिये
सम्पर्क करें : गांधीनगर कार्यालय
403, अखबार भवन, सेक्टर-11, गांधीनगर- 382011.
अहमदाबाद कार्यालय : 4, अवनी हाउस, मिठाखली रेलवे क्रॉसिंग के पास, मिठाखली गाम, अहमदाबाद - 380006.
मोबाईल नं. : 93288 95485
email:- patnagaruday@gmail.com

कार्यवाहक सम्पादक : कनकभाई पंड्या •Published at 1-503, Pramukh Aura, Nr. Pramukh Nagar Bunglows, Pramukh Nagar Road, Kh-0 Road, Sargasan Char Rasta, GANDHINAGAR (GUJ) • email :- patnagaruday@gmail.com

डिफेंस सेक्टर में मोदी सरकार का बड़ा कदम !

फ्रांस के साथ डील से भारतीय कंपनियों को होगा बड़ा फ़ायदा

एजेंसी - नई दिल्ली,

भारत के सबसे बड़े डिफेंस खरीद प्रोग्राम में से एक, 114 राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट्स की डील अब एक अहम पड़ाव पर पहुँच गई है। फ्रांस ने इस डील के लिए भारत को अपना डिटेल्ड टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोज़ल सौंप दिया है।

रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायु सेना (IAF) का एक्विजिशन विंग अभी इस संभावित डील का डिटेल्ड मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये है।

सूत्रों के मुताबिक, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की यह डील अभी रक्षा मंत्रालय के एक्विजिशन विंग और भारतीय वायु सेना के विचाराधीन है। फ्रांसीसी प्रपोज़ल की मुख्य बात भारत में बड़े पैमाने पर लोकल प्रोडक्शन की योजना है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने इस साल मई में सरकार-से-सरकार खरीद रूट के तहत फ्रांस को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल (RFP) भेजा था, जिसके जवाब में फ्रांस ने यह प्रपोज़ल सौंपा है।

प्रपोज़ल के अनुसार, 114 राफेल जेट्स में से 94 का निर्माण भारत में भारतीय इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के सहयोग से किया जाएगा। इस मेगा-डील में, फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी डसॉल्ट एविएशन, स्स्ष्ट, जेटस्टार और ऋढ्रू जैसी अन्य प्रमुख फ्रांसीसी डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी। भारत सरकार इस डील में स्वदेशी कंटेंट बढ़ाने और भारत में बने हथियारों को शामिल करने पर खास ज़ोर दे रही है। इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारत में स्थित डिफेंस सेक्टर की 22 कंपनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा होगा।

भारत की योजना राफेल जेट को स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से लैस करने की है, जिसमें छजंथी (Chhajanthi) एयर-टू-एयर मिसाइल भी शामिल है। डिफेंस एक्सपर्ट्स और वायु सेना के अधिकारी प्रपोज़ल में इस प्रावधान का बारीकी से मूल्यांकन कर रहे हैं।

भारतीय वायु सेना लंबे समय से अपने बेड़े में एडवांस्ड फाइटर जेट्स की कमी का सामना कर रही है। अगर 3.25 लाख करोड़ रुपये की यह डील फाइनल हो जाती है, तो इससे न केवल वायु सेना की कॉम्बैट क्षमताएँ बढ़ेंगी, बल्कि भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी आगे बढ़ेगा। भारत सरकार अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट देश में ही बना रही है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि युद्ध जैसी मुश्किल स्थिति में भारत को बाहरी मदद पर निर्भर न रहना पड़े और हथियारों व उपकरणों की कमी का सामना न करना पड़े। साथ ही, ज़रूरी उपकरण भारत में बनने के कारण उन्हें तेज़ी से उपलब्ध कराया जा सकता है। पहले भारत के पास रूसी युद्धपोत थे, लेकिन उनकी मशीनरी यूक्रेन में बनी थी। इसलिए, रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने उन सामानों की सप्लाई रोक दी। इसके बाद, अब ज़्यादातर चीज़ों को देश में ही बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।

भारत एक खास उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा

एजेंसी - नई दिल्ली,

15 अगस्त को जब टीम इंडिया गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ़ उतरेगी, तो वह इतिहास रचेगी। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गाले में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। यह भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक 600वां टेस्ट मैच होगा। इस उपलब्धि के साथ, भारत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खास क्लब में शामिल हो जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसने 600 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। भारत 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ़ दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलेगा। ऋफ़ाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए यह सीरीज़ अहम है। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच गाले स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 23 से 27 अगस्त के बीच कोलंबो में खेला जाएगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 600 या उससे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। गाले में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया का 600वां टेस्ट मैच होगा। इसके साथ ही भारत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खास रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगा।

पाकिस्तान ने गुजरात बॉर्डर पर सर क्रीक में चीनी ड्रोन और होवरक्राफ्ट तैनात किए-सुरक्षा का खतरा

एजेंसी - इस्लामाबाद,

चीन ने अब पाकिस्तान को भारत की पश्चिमी सीमा पर तनाव पैदा करने के लिए उकसाया है, जबकि पाकिस्तान पहले से ही भारत की उत्तरी सीमा पर जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब तक आतंकवाद फैला रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करके भारत को परेशान कर रहा है। अब उसकी नज़र पश्चिमी सीमा पर भी है और वह अरब सागर में भारतीय नौसेना को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान को उकसा रहा है। इसी योजना के तहत, पाकिस्तान तुर्की और चीन की मदद से सर क्रीक में तेज़ी से अपना नौसैनिक और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। पाकिस्तान नौसेना ने अबाबील प्रोजेक्ट के तहत तुर्की और चीन की मदद से कच्छ सीमा के पास सर क्रीक में अपने ड्रोन और होवरक्राफ्ट भी तैनात किए हैं। इसके साथ ही, उसने नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो भी तैनात किए हैं, जिससे भारत की समुद्री सीमा पर सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान का यह विस्तार अबाबील-द डिवाइन स्ट्राइक नाम के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के काम की देखरेख खुद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत, पाकिस्तान ने सर क्रीक में अपने नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो तैनात किए हैं। ये कमांडो एक समुद्री स्पेशल ऑपरेशन फोर्स हैं, जिन्हें समुद्र, हवा और ज़मीन पर हाई-रिस्क मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। चीन

और तुर्की इस सैन्य आधुनिकीकरण में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तुर्की ड्रोन, चीनी आधुनिक होवरक्राफ्ट और तेज़ रफ़्तार वाली नौसैनिक नावों के साथ-साथ अत्याधुनिक रॉकेट और एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रहा है। तुर्की ड्रोन विस्फोटक ले जाने में सक्षम हैं और इनका इस्तेमाल निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, अबाबील प्रोजेक्ट में एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, जो सर क्रीक इलाके और अरब सागर में पाकिस्तान सेना की नई बनी रॉकेट फोर्स के साथ मिलकर काम करेगा। इस सिस्टम का मकसद बाहरी खतरों को रोकना है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान ने सर क्रीक और अरब सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी को चुनौती देने के लिए अपने समुद्री ऑपरेशनों में बिना पायलट वाले हवाई और समुद्री ड्रोन शामिल किए हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि चीन और तुर्की दोनों ही पाकिस्तानी सेना को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे पाकिस्तान को अत्याधुनिक सैन्य उपकरण और तकनीक सप्लाई कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, चीन ने पाकिस्तान को पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी सौंप दी है। इससे अरब सागर में पाकिस्तान की स्टेल्थ क्षमता (यानी दुश्मन की नज़र से बचकर निकलने की क्षमता) और सेकंड स्ट्राइक क्षमता (यानी दुश्मन के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता) बेहतर होगी। इसके अलावा, इस्लामाबाद ने अपनी नौसेना के बेड़े को आधुनिक बनाने के एक बड़े प्रोग्राम के तहत चीन के एडवांस्ड %तुगरिल क्लास% फ्रिगेट्स को भी शामिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान नेवी ने सर क्रीक के पास बांधा धोरा और हरामी धोरा इलाकों के बीच कई समुद्री सुरक्षा चौकियां भी बनाई हैं। सर क्रीक और अरब सागर में दर्जनों कोस्टल डिफेंस बोट्स, मरीन असॉल्ट क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, नेवल शिप्स और तेज़ रफ़्तार पेट्रोल बोट्स तैनात की गई हैं और नौसेना ने गश्त भी बढ़ा दी है।

भारतीय रेलवे ने भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन पर सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा पैकेज लॉन्च किया

एजेंसी - नई दिल्ली,

भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत आने वाली नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक खास भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन पर सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा नाम का एक नया आध्यात्मिक टूरिज्म पैकेज लॉन्च किया है। यह खास यात्रा दिल्ली से शुरू होगी और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं को 7 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका मिलेगा और फिर यह दिल्ली वापस आएगी। इस आध्यात्मिक यात्रा में, श्रद्धालु सबसे पहले उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। उज्जैन में रात बिताने के बाद, यात्रा खंडवा के लिए आगे बढ़ेगी, जहाँ नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जाएँगे। इसके बाद, तीर्थयात्री ट्रेन से रात भर का सफर करके गुजरात के द्वारका पहुँचेंगे। गुजरात पहुँचने पर, श्रद्धालु भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर और रुक्मिणी देवी मंदिर के दर्शन करेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका के दर्शन के बाद, ट्रेन सोमनाथ के लिए रवाना होगी। तीर्थयात्री विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, सोमनाथ बीच और भालका तीर्थ के दर्शन करेंगे।

संपादकीय

कोर इंडस्ट्रीज़ इंडेक्स

देश के दूसरे आर्थिक पैमानों की तरह ही, कोर इंडस्ट्रीज़ इंडेक्स भी अर्थव्यवस्था की स्थिति को उतना ही सटीक और ताज़ा दिखाता है। नेशनल अकाउंट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे दूसरे डेटा इस साल की शुरुआत में अपडेट किए गए थे। यह अलग बात है कि इन कामों में भी काफी देरी हुई थी। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि ह्ठ सरकार कोई भी डेटा जारी करने से पहले घबराती है। क्या सरकार को इस बात की चिंता है कि कहीं असलियत सामने न आ जाए और जो रंगीन तस्वीर हमने पेश की है, वह गलत साबित न हो जाए ? सरकार की यह नासमझी है कि वह जनता को सिर्फ़ चाँद-तारे दिखाती है। असलियत यह है कि जनता हज़ारों आँखों से सब कुछ देखती है। सरकार को खुद जनता की नज़रों से हालात को देखने की ज़रूरत है। डेटा एक ऐसी अहम चाबी है जिसके बिना प्लानिंग और उसे लागू करना, दोनों ही अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। किसी भी देश के लोकतंत्र की असली परीक्षा यही है कि सरकार असली डेटा के साथ छेड़छाड़ न करे। मोदी सरकार पिछले बारह सालों से बेरोज़गारी के डेटा के साथ छेड़छाड़ करती रही है, फिर भी सच हमेशा सामने आ ही जाता है। ढ्ढष्टढ्ढ ने अब देश के पैमानों की इस लिस्ट में एक और पैमाना जोड़ दिया है। इसका जून का डेटा एक नई सीरीज़ पर आधारित है जिसमें अपडेटेड बेस ईयर, अतिरिक्त सेक्टरों को शामिल करना और बदले हुए वेटेज और तरीके शामिल हैं। इन कोर इंडस्ट्रीज़ का प्रदर्शन अर्थव्यवस्था की सेहत का एक अहम पैमाना है। नई सीरीज़ में आयरन सेक्टर को शामिल करने से, पहले के आठ सेक्टर अब नौ हो गए हैं। स्टील और कोयला सेक्टर के मापने के तरीके में भी बदलाव किया गया है ताकि पहले होने वाली %डबल काउंटिंग% (एक ही चीज़ की दो बार गिनती) को खत्म किया जा सके। एक सेक्टर के जुड़ने से इंडेक्स में सेक्टरों के वेटेज का बंटवारा तो बदला ही है, लेकिन अंतिम वेटेज आर्थिक गतिविधियों में बड़े बदलावों को भी दिखाते हैं। कोयला और नेचुरल गैस सेक्टर का वेटेज लगभग आधा होकर क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर, इंडेक्स में बिजली सेक्टर की हिस्सेदारी अब 20 प्रतिशत से कम से बढ़कर 30 प्रतिशत से ज़्यादा हो गई है। यह शायद बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती हिस्सेदारी को दिखाता है, जबकि बिजली की मांग भी तेज़ी से बढ़ रही है। जून 2026 में इंडेक्स का प्रदर्शन ऐसा रहा कि यह पाँच महीने के सबसे ऊँचे स्तर 5त्न पर पहुँच गया।

आदिवासी समुदाय ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की

दाहोद में फर्जी ST सर्टिफिकेट घोटाला सामने आया

एजेंसी - दाहोद,

दाहोद जिले के सिंगवद और संजेली तालुका में फर्जी अनुसूचित जनजाति (ST) सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी लाभ लेने का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोपों के अनुसार, मूल रावल (बख्शी पंच) समुदाय के एक परिवार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी, स्थानीय निकाय चुनाव, पेट्रोल पंप आवंटन और मेडिकल में एडमिशन जैसे लाभ हासिल किए हैं। इस पूरी घटना ने सरकारी दस्तावेजों के वेरिफिकेशन प्रोसेस और सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, कमलेश कुमार रामसिंहभाई रावल और उनके परिवार के सदस्यों पर तलाटी-कम-मंत्री और मामलतदार कार्यालयों की मिलीभगत या लापरवाही से स्ञ्ज सर्टिफिकेट हासिल करने का आरोप है। कहा जा रहा है कि इन सर्टिफिकेट के आधार पर परिवार के सदस्यों ने कई सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ उठाया है।

आरोपों के मुताबिक, परिवार के एक सदस्य को लिमडी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर सरकारी नौकरी मिली है, जबकि दूसरे सदस्य को फतेपुरा में तलाटी-कम-मंत्री की सरकारी नौकरी मिली है। यह भी पता चला है कि उन्होंने संजेली ग्राम पंचायत में सरपंच के तौर पर प्रतिनिधित्व किया है।

इतना ही नहीं, स्ञ्ज आरक्षण के तहत पेट्रोल पंप आवंटन और मेडिकल की पढ़ाई में एडमिशन के दावे भी किए गए हैं। इसके कारण आरोप लगाया गया है कि मूल आदिवासी समुदाय के योग्य उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ा है।

विपक्षी पार्टी और स्थानीय आदिवासी संगठनों का दावा है कि स्कूल और राजस्व रिकॉर्ड में परिवार की जाति स्पष्ट रूप से रावल (बख्शी पंच) दर्ज है। यह भी कहा गया है कि ये जानकारी संजेली तालुका के कुमार प्राइमरी स्कूल के पुराने रिकॉर्ड और मंडेर गांव के राजस्व दस्तावेजों में मौजूद है। हालांकि, स्ञ्ज सर्टिफिकेट कैसे जारी किए गए, इस पर कई सवाल उठाए गए हैं।

इस पूरे मामले में, आदिवासी समुदाय ने राज्य सरकार, आदिवासी विकास विभाग और गुजरात विजिलेंस कमीशन से निष्पक्ष और उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है।

अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं, तो फर्जी सर्टिफिकेट रद्द करने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अवैध रूप से हासिल किए गए सरकारी लाभ वापस लेने की मांग की जा रही है। स्थानीय आदिवासी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए, तो मूल आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए ज़बरदस्त आंदोलन शुरू किया जाएगा।

हालाँकि, इन आरोपों के संबंध में संबंधित सरकारी अधिकारियों या आरोपी पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पूरे मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

झील में आधे पानी में खड़े होकर रामधुन गाई

एजेंसी - राजकोट,

राजकोट जिले के गोंडल तालुका के चोरडी गाँव की चरागाह ज़मीन पर जेटको (Jetco) कंपनी द्वारा बिजली के खंभे लगाने के काम के ख़िलाफ़ किसानों का गुस्सा चरम पर है। विरोध के दूसरे दिन भी स्थानीय किसान और ग्रामीण इकट्ठा हुए और प्रशासन के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया। चूँकि यह काम बिना उचित प्रतिनिधित्व और समझौते के किया जा रहा है, इसलिए इस इलाके के किसानों में प्रशासन के प्रति बहुत नाराज़गी है।

आंदोलनकारी किसानों ने श्मशान घाट के पास झील के पानी में आधी जल समाधि लेकर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। पानी में खड़े होकर किसानों ने तबला और मंजीरा की थाप पर रामधुन गाकर प्रशासन की नीतियों का विरोध किया। चोरडी के अलावा, गोमटा, वेकारी, पाटीदल और त्राकुडा जैसे आस-पास के गाँवों के 200 से ज़्यादा किसान, सरपंच और स्थानीय नेता भी पूरे जोश के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए।

आंदोलनकारी किसानों ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बड़े नेताओं और प्रमुख उद्योगपतियों की ज़मीन को बचाने के लिए पावर लाइन का मूल रास्ता 156 किलोमीटर तक बदल दिया गया है। प्रशासन के इस फ़ैसले के कारण आम और छोटे किसानों को ज़मीन और खेती में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कलेक्टर ने अगली 20 तारीख को अपनी बात रखने का समय दिया है, फिर भी किसान इस बात से नाराज़ हैं कि बिना किसी लिखित आदेश के पुलिस बल के साथ ज़बरदस्ती काम जारी रखा जा रहा है।

हालात की गंभीरता को देखते हुए गोंडल तालुका पुलिस ने घटनास्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। किसानों ने साफ़ चेतावनी दी है कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कानूनी समिति उनकी ज़मीन और नुकसान के लिए उचित मुआवज़े पर फ़ैसला नहीं ले लेती। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी जायज़ माँगें पूरी नहीं हुईं, तो वे आने वाले दिनों में गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को और तेज़ करेंगे।

जामनगर में फ़ूड डिपार्टमेंट ने पिज़्ज़ा पार्लर और स्नैक शॉप्स पर छापेमारी की

एजेंसी - जामनगर,

जामनगर शहर में नागरिकों की सेहत की सुरक्षा और खाने-पीने की चीज़ों की क्वालिटी बनाए रखने के लिए, फ़ूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के तहत, फ़ूड अधिकारियों की एक टीम ने जामनगर शहर के अलग-अलग इलाकों में स्नैक शॉप्स, पिज़्ज़ा पार्लर, रेस्टोरेंट और फ़ास्ट फ़ूड सेंटर्स पर अचानक छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने भी चेकिंग शुरू की। इस जांच के दौरान, अधिकारियों को एक स्नैक शॉप में रिटेल बिक्री के लिए रखा गया एनालॉग चीज़ (नकली चीज़) मिला। इसके अलावा, जामनगर शहर में एक पिज़्ज़ा पार्लर की चेकिंग के दौरान वहां लगभग 12.50 किलो एनालॉग चीज़ मिला। फ़ूड डिपार्टमेंट ने तुरंत इस 12.50 किलो एनालॉग चीज़ को ज़ब्त कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए TNSZR फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर एन. पी. जसोलिया ने कहा कि राज्य सरकार ने एनालॉग चीज़ और पनीर के इस्तेमाल को लेकर खास गाइडलाइंस दी हैं। अगर कोई व्यापारी एनालॉग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए ग्राहकों को इसके बारे में साफ़ जानकारी देना ज़रूरी है। असली चीज़ या प्राकृतिक दूध से बने पनीर के नाम पर एनालॉग प्रोडक्ट्स बेचकर ग्राहकों को धोखा देना फ़ूड सेफ्टी कानून का गंभीर उल्लंघन है। फ़ूड डिपार्टमेंट की इस अचानक छापेमारी की वजह से शहर के पिज़्ज़ा पार्लर, फ़ास्ट फ़ूड वेंडर्स और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई व्यापारियों ने अपना स्टॉक खुद ही चेक करना शुरू कर दिया है। फ़ूड डिपार्टमेंट ने सभी व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ग्राहकों को सिर्फ़ शुद्ध, ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का चीज़ और पनीर ही परोसा जाए। आने वाले दिनों में भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ़ ऐसी ही रैंडम चेकिंग जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ता अधिकार - सिर्फ़ गारंटी और वारंटी तक सीमित नहीं

अक्सर जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उस पर कोई गारंटी या वारंटी नहीं मिलती, और घर लाने पर पता चलता है कि वह ठीक नहीं है, तो ज़्यादातर लोग खुद को समझा लेते हैं कि अब दुकानदार के पास वापस जाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि इस चीज़ पर तो कोई गारंटी या वारंटी मिली ही नहीं थी ? कई बार दुकानदार अपनी दुकान में बोर्ड लगा देते हैं कि बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। ये दोनों ही बातें गलत हैं। जिन चीज़ों पर हमें लिखित गारंटी या वारंटी का अधिकार नहीं मिलता, उनके लिए भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) हमें यह अधिकार देता है कि अगर उसकी क्वालिटी खराब है या वह हमारी जान के लिए सुरक्षित नहीं है, तो हमें न सिर्फ़ सामान वापस करने का, बल्कि उसके लिए मुआवज़ा पाने का भी अधिकार है। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में ऐसा बोर्ड नहीं लगा सकता कि वह बिका हुआ सामान वापस नहीं लेगा। यह कानूनी रूप से गलत है। ऐसे बोर्ड के बावजूद, अगर आप किसी ऐसी दुकान से सामान खरीदते हैं जहाँ लिखा है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा, तब भी आपके उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा होती है। यानी, आपकी खराब चीज़ न सिर्फ़ बदली जाएगी, बल्कि अगर आप बदले में कोई दूसरी चीज़ नहीं लेना चाहते, तो आपके पैसे भी वापस कर दिए जाएँगे। साथ ही, कुछ मामलों में दुकानदार पर जुर्माना भी लग सकता है और ग्राहक को मुआवज़े के तौर पर अतिरिक्त रकम भी मिल सकती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत, उपभोक्ताओं को ये अधिकार मिले हैं:-

* जान और सेहत के लिए सुरक्षित सामान या सेवाएँ पाने का अधिकार। इसका मतलब है कि अगर खरीदी गई कोई चीज़ जान और सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है, तो उपभोक्ता अधिकारों के तहत आपको न सिर्फ़ दूसरी और सुरक्षित चीज़ पाने का अधिकार है, बल्कि हुई परेशानी के लिए मुआवज़ा पाने का भी अधिकार है। भले ही खरीदी गई चीज़ पर किसी भी तरह की वारंटी या गारंटी न हो। * आपको दुकानदार से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सभी तरह की सही जानकारी पाने का अधिकार है, जैसे उसकी क्वालिटी, मात्रा, कीमत, बनने की तारीख और एक्सपायरी डेट वगैरह। अगर खरीदी गई चीज़ पर ये बातें कहीं नहीं लिखी हैं, तो पहली बात तो यह कि उपभोक्ता अधिकारों के नियमों के तहत वह प्रोडक्ट संदिग्ध माना जाएगा, और दूसरी बात यह कि आपके खरीदे गए प्रोडक्ट के लिए आपको सभी तरह के उपभोक्ता अधिकार मिलेंगे। * दुकानदार आपको किसी खास ब्रांड का सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता और न ही बार-बार इसके लिए ज़ोर डाल सकता है। एक ग्राहक के तौर पर, आपको अपनी पसंद का सामान खरीदने का पूरा अधिकार है।

* अगर खरीदे गए सामान में कोई खराबी या समस्या मिलती है, तो दुकानदार के लिए न सिर्फ़ आपकी शिकायत सुनना ज़रूरी है, बल्कि उस शिकायत का समाधान करना भी अनिवार्य है।

* अगर खरीदा गया सामान खराब निकलता है, तो हर ग्राहक को पैसे वापस पाने, सामान ठीक करवाने, उसे बदलवाने या मुआवज़ा पाने का पूरा अधिकार है। ग्राहकों को अपने अधिकारों और कानूनी मामलों के बारे में पूरी जानकारी पाने का भी अधिकार है। लोगों में यह आम गलतफहमी है कि अगर आपने बिना गारंटी या वारंटी के कोई चीज़ खरीदी है, तो उस पर आपके कोई उपभोक्ता अधिकार नहीं हैं। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है और वह खराब निकलती है, या दुकानदार ने उसके बारे में गलत जानकारी दी है, या खरीदा गया सामान नकली या घटिया क्वालिटी का निकलता है और प्रोडक्ट के बारे में बताई गई क्वालिटी के मुताबिक नहीं होता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। भले ही आपके पास कोई लिखित गारंटी या वारंटी न हो। लेकिन हाँ, इसके लिए आपके पास खरीदे गए सामान का बिल होना ज़रूरी है। इसके लिए सिर्फ़ पारंपरिक बिल ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन ऑर्डर रिकॉर्ड, UPI कार्ड, पेमेंट रिकॉर्ड, पैकेजिंग, दुकानदार का WhatsApp या स्रूस् मैसेज या आपकी खरीद का कोई गवाह जैसे सबूत भी काफी हैं। हालाँकि, बिल सबसे मज़बूत और प्रामाणिक दस्तावेज़ है। साथ ही, एक उपभोक्ता के तौर पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर ऐसा बोर्ड नहीं लगा सकता जिस पर लिखा हो, एक बार बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। असल में, ऐसा बोर्ड उपभोक्ता के कानूनी अधिकारों के खिलाफ़ एक साज़िश है। इस साज़िश की वजह से उपभोक्ताओं के अधिकार छीने नहीं जा सकते। अगर सामान खराब है, तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। अगर खरीदा गया सामान नकली या डुप्लिकेट निकलता है, अगर विज्ञापन में दिखाई गई प्रोडक्ट की खूबियाँ असलियत में नहीं मिलती हैं, या कुछ और कहकर कोई दूसरा प्रोडक्ट दिया जाता है या स्क्रक्क्से ज़्यादा कीमत वसूली जाती है, तो इन सभी स्थितियों में आप उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं और समाधान जल्द से जल्द आपके पक्ष में होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि शिकायत कहाँ करें, इसलिए इस जानकारी को ध्यान से पढ़ें:-

सबसे पहले, उस दुकानदार या कंपनी से शिकायत करें जिससे आपने सामान खरीदा है या जिसने उसे बनाया है। यह शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए। अपनी लिखित शिकायत consumerhelpline.gov.in पर दर्ज कराएँ। ग्राहकों के लिए तीसरा कदम ऑनलाइन कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कराना है। इसके लिए adakhil.nic.in पर शिकायत दर्ज करें और हाँ, ये सभी अधिकार छोटी-मोटी खरीदारी पर भी लागू होते हैं। चाहे आपने 200 रुपये का इलेक्ट्रिक चार्जर खरीदा हो, 500 रुपये का मिक्सर का कोई पार्ट खरीदा हो या 1000 रुपये की कोई मोबाइल एक्सेसरी खरीदी हो। आपको हर तरह की खरीदारी पर ये अधिकार मिलते हैं। एक बात जान लें कि कानून में, क्वालिटी और इस्तेमाल के बारे में सेलर (विक्रेता) द्वारा दी गई गारंटी, वारंटी से ज़्यादा ज़रूरी होती है। यह एक अधिकार है; यानी, अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाली चीज़ के तौर पर बेचा जाता है, तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह वही काम करे जिसके लिए उसे खरीदा गया था।

लेकिन अगर उसे खरीदने और घर लाने के बाद भी हमारा मकसद पूरा नहीं होता, तो एक ग्राहक के तौर पर आपके पास यह अधिकार है कि आप उस चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ ले लें, या उसी चीज़ का कोई दूसरा नया पीस ले लें, या फिर खरीद के लिए दिए गए पैसे वापस पा लें। ग्राहक के पास ये सभी अधिकार होते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि ग्राहक अपने अधिकारों को समझे और उनके लागू होने को सुनिश्चित करे।

US समेत ग्लोबल इक्विटी में निवेश

हाल ही में एलन मस्क की कंपनी SpaceX का IPO ज़बरदस्त रहा और लिस्टिंग के बाद इसके शेयर की कीमतें भी बढ़ीं। अब भारत में न सिर्फ़ बड़े निवेशक, बल्कि छोटे निवेशक भी ऐसी कंपनियों में निवेश करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसमें निवेश करने का एक ज़रिया इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। मस्क के वेंचर्स की चर्चा आजकल ज़ोरों पर है; ट्रिलियनेयर एलन मस्क भारतीय घरों में, और खासकर फाइनेंशियल मार्केट में चर्चा का विषय बन गए हैं। सिर्फ़ मस्क की कंपनी ही नहीं, भारतीय निवेशक कई ग्लोबल-स् कंपनियों के शेयरों में निवेश करने में भी तेज़ी से दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

अगर यह वर्ग सीधे स्-लिस्टेड इक्विटी में निवेश करना चाहे, तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुज़रना होगा और लागत भी ज़्यादा आएगी, लेकिन म्यूचुअल फंड के ज़रिए यह काम कम पैसे में और आसानी से किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि आपके पोर्टफोलियो में स् कंपनियों के शेयर भी होने चाहिए। अगर आप सीधे निवेश कर सकते हैं, तो सीधे करें; वरना म्यूचुअल फंड स्कीम के ज़रिए स्इक्विटी मार्केट में निवेश करना बेहतर है।

निवेश विशेषज्ञ अब सलाह देने लगे हैं कि निवेशकों को अपने निवेश योग्य फंड का लगभग पांच प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में रखना चाहिए। जहाँ एक तरफ़ हमारा शेयर बाज़ार बेहतर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ ज़्यादातर निवेशक और ट्रेडर ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाज़ारों की भी बात कर रहे हैं, जिनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार भारत में शेयर बेच रहे हैं और अपना पैसा इन ग्लोबल बाज़ारों में लगा रहे हैं। ताइवान का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन भी भारतीय बाज़ार से ज़्यादा हो गया है। मार्केट कैप के मामले में ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में पाँचवें स्थान पर आ गया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लोबल निवेशक भारतीय बाज़ार के बजाय ताइवान और दक्षिण कोरिया के कैपिटल मार्केट में ज़्यादा निवेश क्यों कर रहे हैं। किन वजहों से ये दोनों बाज़ार आकर्षक और तेज़ी वाले बने हुए हैं ? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ढ्ढ) और सेमीकंडक्टर सेक्टर की कंपनियों का मुख्य योगदान है, जिससे उनके मार्केट कैप में भी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय निवेशक विदेशी या ग्लोबल बाज़ारों में ऐसी लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में निवेश करके इस तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। भारत में इस तरह के निवेश के मौके बहुत कम या सीमित हैं। भारतीय निवेशकों के पास यह निवेश करने के तीन तरीके हैं:- सबसे आसान तरीका इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के ज़रिए है; दूसरा तरीका गिफ्ट सिटी में मौजूद म्यूचुअल फंड के ज़रिए है; और तीसरा तरीका ज़्यादा मुश्किल और महंगा है, जिसमें निवेशक किसी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस में अपना अकाउंट खोलकर सीधे विदेशी बाज़ारों की इक्विटी या श्वञ्जस्न में निवेश कर सकते हैं। इनमें सबसे आसान तरीका ऐसे लोकल म्यूचुअल फंड में निवेश करना है जो LAMSM या SIP के ज़रिए ग्लोबल मार्केट इक्विटी में निवेश करते हैं; इन फंड्स के ज़रिए भारतीय पैसा अमेरिका, जापान, ब्राज़ील, ताइवान, चीन और यूरोप जैसे बाज़ारों में जाता है।

भारतीय निवेशक इन फंड्स में रुपये में निवेश कर सकते हैं। दूसरे तरीके में, वे गिफ्ट सिटी में मौजूद म्यूचुअल फंड के ज़रिए निवेश कर सकते हैं। हालाँकि, चूँकि इस तरीके में निवेश की सीमा ज़्यादा है, इसलिए यह सिर्फ़ बड़े निवेशकों के लिए ही किफायती है। अभी गिफ्ट सिटी में ष्ठस्क्क ग्लोबल इक्विटी फंड, एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड और पराग पारिख ढ्ढस्नस्ष्ट स्&क्क-500 फंड ऑफ़ फंड्स के साथ-साथ पराग पारिख ढ्ढस्नस्ष्ट नैस्डैक-100 फंड ऑफ़ फंड्स उपलब्ध हैं। जल्द ही गिफ्ट सिटी में कुछ और म्यूचुअल फंड भी आने वाले हैं, जो ग्लोबल इक्विटी में निवेश के मौके देंगे। मौजूदा हालात में, क्या विदेशी इक्विटी बाज़ारों में निवेश करना बेहतर है या लोकल स्टॉक मार्केट में निवेश करना फायदेमंद है ? जानकारों का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी कई अच्छी कंपनियों के साथ तेज़ी से बढ़ रही है। हालाँकि, ग्लोबल मार्केट कैप में इसकी हिस्सेदारी बहुत कम है। अभी भारत में कई अहम सेक्टर और उनकी ग्लोबल कंपनियाँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते भारतीय निवेशकों समेत ग्लोबल निवेशक भी ऐसी कंपनियों में निवेश करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। फिर भी, भारतीय निवेशकों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे भारतीय शेयरों के अलावा ऐसे ग्लोबल शेयरों पर भी ध्यान दें; यानी दोनों बाज़ारों में, और भारतीय बाज़ार में भी, निवेश के बड़े मौके मौजूद हैं।

हर घर तिरंगा अभियान-2026

9 से 14 अगस्त तक जिला एवं तहसील स्तर पर 'हर घर तिरंगा' अभियान- तिरंगा यात्रा, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं तथा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम आयोजित होंगे

ब्यूरो रिपोर्ट -जे. बी. टांक, पत्रकार, सूरत,

सूरत जिले में आगामी 9 से 14 अगस्त तक विभिन्न विभागों द्वारा विविध कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों के माध्यम से 'हर घर तिरंगा' अभियान आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में महापौर श्रीमती मायाबेन मावाणी की उपस्थिति में जिला कलेक्टर श्री तेजस परमार की अध्यक्षता में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।

जिला कलेक्टर ने नागरिकों में राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान में शहर एवं जिले के अधिकतम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित कर व्यापक जनभागीदारी दर्ज कराने का आह्वान किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सूरत जिले में तिरंगे के सम्मान एवं गरिमा को बनाए रखते हुए सभी कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किए जाएं।

कलेक्टर ने कहा कि शहर, जिला, तहसील, नगरपालिकाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों, दुकानों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी एवं निजी कार्यालयों तथा सामाजिक संस्थाओं सहित प्रत्येक स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, ताकि लोगों में राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र के प्रति गौरव और देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल हो।

उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं तथा युवा एवं महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।

उप जिला कलेक्टर (प्रोटोकॉल) श्री ए.पी. गोहिल ने बताया कि सूरत जिले में 14 अगस्त तक विभिन्न विभागों द्वारा विविध कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों के साथ 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के सहयोग से भाषण प्रतियोगिता, क्विज, निबंध लेखन, प्रभात फेरी, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिताओं सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' भी मनाया जाएगा, जिसमें देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री समीर मोदी, सूरत महानगरपालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राजन पटेल, पुलिस आयुक्त श्री वाबांग जमीर, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राजन गढ़िया, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर श्री विजय रबारी, प्रांत अधिकारियों सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को गति देकर छोटे एवं गरीब हथकरघा कारीगरों के उत्पादों की खरीदी के जरिए आत्मनिर्भर भारत के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिबद्धता

सूचना विभाग द्वारा गांधीनगर,

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से मनाए जा रहे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (नेशनल हैंडलूम डे) के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर स्थित गरवी गुर्जरी स्टोर जाकर हथकरघा उत्पादों की खरीदारी की।

प्रधानमंत्री ने इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर देशवासियों से हैंडलूम उत्पाद खरीदकर ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने में सहभागी होने के साथ ही अपनी समृद्ध हथकरघा बुनाई की विरासत को प्रोत्साहन देने की अपील की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री की इस अपील पर गांधीनगर में राज्य सरकार के उपक्रम गरवी गुर्जरी से हैंडलूम उत्पादों की खरीदी की।

मुख्यमंत्री ने गरवी गुर्जरी के कर्मचारियों के साथ संवाद किया और बिक्री के लिए रखे गए विभिन्न हैंडलूम उत्पादों की जानकारी हासिल की।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम.के. दास तथा गुजरात राज्य हथकरघा और हस्तकला निगम गरवी गुर्जरी की प्रबंध निदेशक और सचिव श्रीमती आर्दा अग्रवाल भी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री का लक्ष्य हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक और कलात्मकता के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार हैंडलूम उत्पादों को 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र के जरिए दुनिया का बाजार उपलब्ध कराना है।

उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में तथा छोटे-ग्रामीण कारीगरों एवं परिवारों को आर्थिक समृद्धि और सम्मान देने के लिए 2015 से प्रतिवर्ष 7 अगस्त को 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की है।

गोबरधन योजना - ग्रामीण गुजरात का 'ग्रीन' फ्यूचर

सूचना विभाग द्वारा गांधीनगर,

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत गुजरात में 'गोबरधन योजना' (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन) पशुपालकों और किसानों के जीवन में एक नया उजियारा ला रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में वर्ष 2023-24 से अब तक कुल 88 क्लस्टरों में 14 हजार से अधिक बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं।

वहीं, वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना को सतत क्रियान्वित कर आगे बढ़ाते हुए राज्य में 25 करोड़ रुपए की लागत से 20 हजार और व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट स्थापित करने की योजना है। इससे ग्रामीण स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद के उपयोग और सर्कुलर इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई मिलेगी। इस प्रकार, गोबरधन योजना ग्रामीण गुजरात के 'ग्रीन' फ्यूचर के रूप में स्थापित हो रही है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के साथ राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी स्कीम 'गोबरधन' को मंजूरी दे दी है।

गुजरात ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक विशेष क्लस्टर मॉडल अपनाया है। इसके तहत राज्य में फेज-1 में 38 क्लस्टर के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), अमूल, बनास और दूधसागर डेयरी जैसी नोडल एजेंसियों के जरिए 7423 व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट सफलतापूर्वक कार्यरत किए गए हैं। जबकि फेज-2 में राज्य सरकार के 100 फीसदी योगदान के तहत 50 क्लस्टरों में 10 हजार व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अंतर्गत गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) और जिला दूध संघों के समन्वय से अब तक 70 फीसदी यानी लगभग 7 हजार बायोगैस प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इस प्रकार, दोनों चरणों में कुल 14 हजार से अधिक बायोगैस प्लांट लगाए गए हैं।

इस योजना के तहत राज्य में 2 घनमीटर क्षमता वाले आधुनिक फ्लेक्सी प्रकार के बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले एचडीपीई (हाई-डेंसिटी पॉलीइथिलीन) मटेरियल से बने इस डाइजेस्टर का इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान और रखरखाव का खर्च भी बहुत कम होता है। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए लाभार्थी को बायोगैस किट के साथ बायोडाइजेस्टर, जियो टेक्सटाइल शीट, गैस पाइप, हाइड्रोजन सल्फाइड (एच 2 एस) फिल्टर, दो बर्नर गैस स्टोव, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व और लाइटर जैसी सारी साधन-सामग्री प्रदान की जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाभार्थी को बायोगैस प्लांट के लिए 25 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जबकि 5 हजार रुपए लाभार्थी को खुद वहन करना होता है।

जानिए गोबरधन योजना और बायोगैस प्लांट के फायदे

यूनिसेफ द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार 2 घनमीटर क्षमता वाले एक बायोगैस प्लांट से सालाना 8 से 10 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है, 18,250 किलोग्राम पशु अपशिष्ट (गोबर) का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन होता है और 834 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आती है। इसके अलावा, रसोई के धुएं से मुक्ति मिलने से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है और बायोस्लरी (जैविक खाद) के उपयोग से रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम होता है और प्राकृतिक कृषि को गति मिलती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व और ग्राम विकास मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया और राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महीड़ा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने पशुओं के गोबर और जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा (बायोगैस) तथा जैविक खाद के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण स्वच्छता, ओडीएफ प्लस (खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखना) गांवों की संकल्पना और नवीकरणीय ऊर्जा को नया बल प्रदान किया है।

गोबरधन योजना से स्वच्छता और समृद्धि - मंजुलाबेन बारड की प्रेरक कहानी

सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ जिले की सुत्रापाड़ा तहसील के रंगपुर गांव निवासी मंजुलाबेन देडाभाई बारड का परिवार पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा है। पहले पशुओं के गोबर का सार्वजनिक खुली जगह में संग्रह होने के कारण गंदगी, दुर्गंध और मक्खी-मच्छरों का उपद्रव बहुत ज्यादा था, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन गया था। 2025-26 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सरकार के सहयोग से उनके घर पर गोबरधन प्लांट लगाया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा क्रियान्वित और जीसीएमएमएफ की ओर से जूनागढ़ की सावज डेयरी के सहयोग से तैयार किए गए इस प्लांट का रखरखाव मंजुलाबेन स्वयं करती हैं।

इस गोबरधन प्लांट के जरिए गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करके स्वच्छ बायोगैस और जैविक खाद (स्लरी) प्राप्त हो रही है, जो 'वेस्ट टू वेल्थ' दृष्टिकोण का एक उत्तम उदाहरण है। अब मंजुलाबेन खाना पकाने के लिए इस स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करती हैं। साथ ही, खेतों में स्लरी का इस्तेमाल बढ़ाने से यूरिया खाद का इस्तेमाल भी कम हुआ है। इस सफल पहल ने न केवल उनके परिवार को स्वच्छ ऊर्जा दी है, बल्कि गांव के अन्य पशुपालकों के लिए भी गोबर के उचित उपयोग और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का एक प्रेरक मॉडल दिया है।

राघव चड्ढा ने अपने पुराने अंदाज़ में वापसी की

एजेंसी - नई दिल्ली,

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच कमीशन के खेल का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि कुछ डॉक्टर मरीज़ों को टेस्ट के लिए किसी खास डायग्नोस्टिक सेंटर भेजते हैं ताकि उन्हें रेफरल कमीशन मिल सके। राज्यसभा में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि यह कुछ डॉक्टरों और डायग्नोस्टिक सेंटरों के बीच एक अनौपचारिक व्यवस्था बन गई है। यह व्यवस्था मरीज़ के इलाज के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रेफर करने और डॉक्टर की जेब में 3,000 रुपये तक पहुंचाने के लिए होती है। कमीशन की एक तय दर है और देश में एजेंटों के ज़रिए एक पूरा समानांतर इंसेंटिव नेटवर्क चल रहा है।

सांसद ने कहा कि इसे अच्छी भाषा में डॉक्टर का रेफरल कमीशन दिखाया जाता है और डायग्नोस्टिक सेंटर की किताबों में इसे मार्केटिंग का खर्च दिखाया जाता है। यह कमीशन आमतौर पर टेस्ट की कुल लागत के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाता है और कुछ जगहों पर तो डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टरों को विदेश यात्रा पर भी भेजते हैं।

इस प्रथा पर मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (MCI), 2002 के कोड ऑफ़ एथिक्स रेगुलेशन 6.4 के तहत रोक लगाई गई थी। इसके बाद, 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रेगुलेशन 2023 के तहत रेफरल कमीशन पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है और 1 से 3 महीने के सस्पेंशन का प्रावधान किया है। बड़े उल्लंघनों के मामले में धोखाधड़ी और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

इस कमीशन का आर्थिक बोझ डायग्नोस्टिक सेंटर खुद नहीं उठाते, बल्कि इसे मरीज़ के बिल में जोड़ दिया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ़ मेडिकल एथिक्स के अनुसार, इस कट मनी प्रथा के कारण मरीज़ का कुल मेडिकल बिल 15 से 20त्न तक बढ़ जाता है।

सदन में इस मुद्दे पर ज़ोर देते हुए सांसद ने कहा कि डायग्नोस्टिक सेंटर मरीज़ को रेफर करने के बदले डॉक्टरों को कमीशन देते हैं। यह पैसा मरीज़ों की जेब से लिया जाता है। मेडिकल पेशे की भाषा में इसे रेफरल कमीशन कहा जाता है। इस प्रथा को रोका जाना चाहिए। सांसद ने स्पष्ट किया कि यह विरोध डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, बल्कि इस कट मनी सिस्टम के खिलाफ है। देश में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और ज़्यादातर डॉक्टर पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर इस रेफरल सिस्टम के जाल में फंसते जा रहे हैं। इस वजह से, गैर-ज़रूरी मेडिकल टेस्ट करवाने का चलन बढ़ रहा है।

प्राकृतिक खेती ने ज़मीन की उत्पादकता, पानी सोखने की क्षमता और गुणवत्ता में काफी सुधार किया है-राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी

सूचना विभाग द्वारा- गांधीनगर,

राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में, राज्य में चल रहे प्राकृतिक खेती अभियान को और अधिक गतिशील बनाने के लिए विभिन्न रणनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी और कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी विशेष रूप से उपस्थित थे।

इस बैठक में राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती अभियान को वास्तव में सफल बनाने के लिए कृषि विभाग और किसानों का मिशन मोड में काम करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती जन-स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा एक पवित्र कार्य है।

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती और पशुपालन एक-दूसरे के पूरक हैं। स्वस्थ पशुधन प्राकृतिक खेती को मज़बूत बनाता है और प्राकृतिक आहार पशुओं के स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता में सुधार करता है।

अपने व्यक्तिगत अनुभव का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद उनके खेत की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.7 प्रतिशत हो गई है। नतीजतन, मिट्टी की उत्पादकता, पानी सोखने की क्षमता और गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरिया और डीएपी के बजाय जीवामृत और ठोस जीवामृत का उपयोग करने से खेती की लागत कम होती है।

गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने कहा कि प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए अमूल, इफको (IFFCO) और गुजकोमासोल (Gujcomasol) जैसे संगठनों की मदद भी ली जा सकती है। अपने खेत में प्राकृतिक खेती के अनुभवों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू की थी, तब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 0.2 से 0.4 प्रतिशत था, जो आज 1 प्रतिशत से अधिक है।

प्राकृतिक खेती से उत्पादित चारे में विटामिन क्ष12 और ष्ठ3 सहित कई पोषक तत्व पाए गए हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद मिट्टी और फसलों में आए बदलावों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

इसके अलावा, बनास डेयरी के प्रतिनिधियों के यूरोपीय देशों के अध्ययन दौरे पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि प्राकृतिक खेती अभियान को ते ? करने के लिए, उन्होंने ऐसे देसी बीजों पर और रिसर्च करने की ?रूरत पर ज़ोर दिया जो प्राकृतिक खेती के लिए सही हों और ज़्यादा पैदावार दे सकें।

उन्होंने राज्य की सभी यूनिवर्सिटीज़ को और बेहतर बीज तैयार करने और ज़्यादा प्राकृतिक मॉडल फ़ार्म बनाने का सुझाव दिया।

बैठक के दौरान, जीवामृत को वैज्ञानिक रूप से स्टैंडर्डाइज़ करने, उसके इस्तेमाल की अवधि बढ़ाने और देसी गायों के गोबर में मौजूद माइक्रोऑर्गेनिज़्म पर रिसर्च के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा, राज्य भर में प्राकृतिक खेती से पैदा हुए उत्पादों की बिक्री के लिए विकसित किए जा रहे बाज़ारों और नए बाज़ार शुरू करने की आने वाली योजनाओं पर भी चर्चा की गई।

बैठक में कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.सी. मीणा, लोक भवन के सचिव श्री मेहुल दवे, राज्य की सभी कृषि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा प्रोजेक्ट, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के सीनियर अधिकारी और बनास डेयरी के अधिकारी शामिल हुए।

गुजरात सरकार ने राजधानी से बाहर राष्ट्रीय-राज्य पर्वों के आयोजक जिले का विकास अनुदान दोगुना किया, अब 15 करोड़ रुपए तक मिलेंगे

सूचना विभाग द्वारा
गांधीनगर,

गुजरात सरकार ने राष्ट्रभक्ति और विकास को एक साथ आगे बढ़ाने वाली अपनी अनूठी परंपरा को और मजबूत करते हुए राजधानी गांधीनगर से बाहर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पर्वों तथा गुजरात राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजक जिले को विकास कार्यों के लिए मिलने वाले अनुदान को दोगुना कर दिया है। अब जिस जिले में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पर्व अथवा गुजरात राज्य स्थापना दिवस का आयोजन होगा; वहाँ ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और महानगर पालिका क्षेत्र के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 10 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक का विकास अनुदान दिया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात में शुरू की गई उस विकास परंपरा को नई गति देने वाला है, जिसमें गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों और गुजरात स्थापना दिवस के गौरवपूर्ण आयोजनों को राजधानी तक सीमित रखने के बजाय राज्य के अलग-अलग जिलों तक पहुँचाया गया है। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू की थी परंपरा वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों तथा गुजरात स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोहों को गांधीनगर से बाहर विभिन्न जिलों में आयोजित करने की परंपरा शुरू की थी। इसी क्रम में पहली बार 15 अगस्त, 2003 को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह गांधीनगर से बाहर पाटण जिले में आयोजित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य केवल राष्ट्रीय पर्वों को राज्य के विभिन्न हिस्सों तक ले जाना ही नहीं था, बल्कि जिस जिले को राज्य स्तरीय समारोह की मेजबानी का अवसर मिले, वहाँ विकास कार्यों को भी गति देना भी था। समय के साथ यह परंपरा गुजरात के प्रशासनिक और विकास मॉडल की एक विशिष्ट पहचान बन गई। विकास अनुदान 2.50 करोड़ से बढ़कर अब 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सीधे नेतृत्व में कार्यरत सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने 06 अगस्त, 2026 को एक संकल्प पारित कर राष्ट्रीय-राज्य पर्व आयोजक जिले की विकास अनुदान राशि दुगुनी करने का निर्णय किया है। इस निर्णय के अनुसार अब राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पर्व अथवा गुजरात राज्य स्थापना दिवस जिस जिले में आयोजित होगा, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) को 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले यह राशि 2.50 करोड़ रुपए थी। इसी प्रकार; उस जिले में स्थित नगर पालिकाओं को शहरी विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी। यदि आयोजन वाला क्षेत्र महानगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो वहाँ 5 करोड़ रुपए तक की राशि महानगर पालिका आयुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी।

इस प्रकार; नए प्रावधान के तहत तीनों विकास क्षेत्रों को मिलाकर कुल 15 करोड़ रुपए तक की विकास राशि उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यानी पहले की तुलना में प्रत्येक मद में 100 प्रतिशत वृद्धि की गई है। यद्यपि; जो आयोजक जिले में महानगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता, वहाँ विकास अनुदान 10 करोड़ रुपए ही दिया जाएगा।

चलथाण नगर प्राथमिक विद्यालय में 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा बाल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

ब्यूरो रिपोर्ट - जे. बी. टांक,
पत्रकार, सूरत,

मिशन वात्सल्य के अंतर्गत संचालित 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा चलथाण स्थित नगर प्राथमिक विद्यालय में बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बाल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की निःशुल्क टोल-फ्री सेवा, उसकी कार्यप्रणाली तथा किसी भी बच्चे के साथ शोषण, बाल मजदूरी, बाल विवाह, भिक्षावृत्ति, घर से भाग जाने, लापता होने अथवा किसी अन्य संकटपूर्ण परिस्थिति में 1098 पर तत्काल संपर्क कर निःशुल्क सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया।

विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के बीच का अंतर सरल भाषा में समझाया गया। साथ ही बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने वाले **POCSO** अधिनियम, 2012 की जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में चुप न रहें, बल्कि किसी विश्वसनीय व्यक्ति, शिक्षक, अभिभावक अथवा 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें।

कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध, बाल मजदूरी एवं भिक्षावृत्ति की रोकथाम, बच्चों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न बाल संरक्षण योजनाओं की भी जानकारी दी गई। साथ ही यह भी समझाया गया कि यदि कोई बच्चा लापता हो जाए तो समय पर पुलिस एवं 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क करने पर बच्चे को शीघ्र खोजने में सहायता मिल सकती है।

इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तर सत्र में उत्साहपूर्वक भाग लेकर बाल सुरक्षा से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

अंत में विद्यार्थियों ने बाल सुरक्षा का संदेश अपने मित्रों, परिवारजनों एवं समाज तक पहुंचाने तथा आवश्यकता पड़ने पर निडर होकर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की सहायता लेने का संकल्प लिया।

सिटीलाइट स्थित साइंस सेंटर में महापौर मायाबेन मावाणी की अध्यक्षता में 'माय हैंडलूम, माय प्राइड' थीम के साथ राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया

ब्यूरो रिपोर्ट - जे. बी. टांक,
पत्रकार, सूरत,

सिटीलाइट स्थित साइंस सेंटर में आयोजित क्राफ्ट रूट प्रदर्शनी के दौरान महापौर मायाबेन मावाणी की अध्यक्षता तथा विधायक संगीताबेन पाटिल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन जरदोश की प्रेरक उपस्थिति में 'माय हैंडलूम, माय प्राइड' थीम के साथ राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया।

यह कार्यक्रम सूरत महानगरपालिका, सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की लेडीज़ विंग, **WICCI** एंटरप्रेन्योर सेल, अमी हैंडीक्राफ्ट्स तथा अवनी साड़ी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। भारतीय विरासत और हैंडलूम कला को सम्मान देने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक हैंडलूम परिधान पहनकर कार्यक्रम में भाग लिया और 'माय हैंडलूम, माय प्राइड' थीम को साकार किया।

इस अवसर पर महापौर मायाबेन मावाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दिन देश के हैंडलूम बुनकरों की कला, कौशल और परिश्रम को सम्मान देने तथा स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहन देकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और आगे बढ़ाने का संदेश देता है। उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक से सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हैंडलूम उत्पादों को प्राथमिकता देने तथा स्वदेशी कारीगरों को प्रोत्साहित करने की अपील की।

राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन जरदोश ने कहा कि वर्ष 1905 में राष्ट्रपिता द्वारा प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन को प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न के साथ नई गति प्रदान की है। स्वदेशी कला और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहित कर देशभर में लोगों को विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हस्तशिल्प एवं कला से जुड़े कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक पहल की गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष क्राफ्ट रूट प्रदर्शनी के साथ राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस का आयोजन होने से शहरवासियों को हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध होने का उत्कृष्ट अवसर मिला है।

कार्यक्रम में अमी हैंडीक्राफ्ट्स की भावनाबेन देसाई, साड़ी ड्रेपिंग एक्सपर्ट हिना घेहानी, अवनी हैंडलूम साड़ी की शिल्पी साध सहित विभिन्न क्षेत्रों की महिला उद्यमियों एवं अग्रणी महिलाओं ने भी उपस्थित रहकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया।

चूहों को पकड़ने वाली ग्लू-ट्रैप के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी पुलिस आयुक्त की अधिसूचना

ब्यूरो रिपोर्ट -जे. बी. टांक,
पत्रकार, सूरत

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत सूरत के पुलिस आयुक्त वाबांग जामीर (आईपीएस) द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, सूरत शहर पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में चूहों को पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली ग्लू-ट्रैप (गोंद वाली जाल) के निर्माण, बिक्री तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 06 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सद्गुरु श्री रामकिशनदास बापू की प्रतिमा प्रतिष्ठा के अवसर पर अमरेली जिले के बाबरा तहसील के गमापीपळिया गांव स्थित श्री बोखला हनुमानजी महाराज आश्रम में दो दिवसीय भव्य धार्मिक महोत्सव का आयोजन

शोभायात्रा, यज्ञ, प्रतिमा प्रतिष्ठा, सुंदरकांड पाठ एवं महाप्रसाद सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया

ब्यूरो रिपोर्ट - जे. बी. टांक,
पत्रकार, अमरेली

अमरेली जिले के बाबरा तहसील के गमापीपळिया गांव स्थित श्री बोखला हनुमानजी महाराज आश्रम में परम पूज्य सद्गुरु श्री रामकिशनदास बापू की पावन प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव एवं यज्ञोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।

इस पावन अवसर पर दो दिवसीय धार्मिक महोत्सव के अंतर्गत यज्ञ, भव्य शोभायात्रा, सुंदरकांड पाठ, प्रतिमा प्रतिष्ठा, बिंब होम तथा महाप्रसाद सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सद्गुरु श्री रामकिशनदास बापू के आशीर्वाद एवं श्री बोखला हनुमानजी महाराज की असीम कृपा से आयोजित इस महोत्सव में संपूर्ण सौराष्ट्र क्षेत्र से संत-महंत, महामंडलेश्वर, धार्मिक अग्रणी तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे।

इस अवसर पर आश्रम परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य संपन्न हुए यज्ञ एवं प्रतिमा प्रतिष्ठा समारोह ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भजन-कीर्तन, संतवाणी एवं विविध धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराई गई। महोत्सव के प्रथम दिन दोपहर 3:00 बजे सद्गुरु श्री रामकिशनदास बापू की प्रतिमा की भव्य शोभायात्रा निकाली गई तथा रात्रि 8:00 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दूसरे दिन प्रातः 7:30 बजे वैदिक विधि-विधान के अनुसार यज्ञ का शुभारंभ हुआ तथा प्रातः 10:30 बजे सद्गुरु श्री रामकिशनदास बापू की प्रतिमा प्रतिष्ठा का मुख्य धार्मिक समारोह संपन्न हुआ। इसके उपरांत प्रातः 11:30 बजे बिंब होम की पवित्र विधि संपन्न कराई गई। दोपहर 12:00 बजे सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई।

यह संपूर्ण धार्मिक महोत्सव श्री बोखला हनुमानजी महाराज आश्रम, ग्राम गमापीपळिया, तहसील बाबरा, जिला अमरेली में संपन्न हुआ।

आयोजन समिति ने बताया कि सद्गुरु श्री रामकिशनदास बापू के आशीर्वाद एवं श्री बोखला हनुमानजी महाराज की कृपा से आयोजित इस महोत्सव ने समाज में धर्म, संस्कार, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का संदेश प्रसारित किया। ऐसे पावन अवसर केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज में एकता, सेवा, संस्कार एवं सद्भावना को भी सुदृढ़ बनाते हैं।

अंत में आयोजन समिति की ओर से पधारे हुए सभी संतों, महंतों, धार्मिक एवं सामाजिक अग्रणियों, श्रद्धालु भक्तों तथा समस्त समाज के लोगों का परिवार सहित उपस्थित होकर सद्गुरु श्री रामकिशनदास बापू के दर्शन, प्रतिमा प्रतिष्ठा महोत्सव, यज्ञ एवं महाप्रसाद का लाभ लेने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया गया तथा सभी को शुभाशीष प्रदान किए गए।

इस संपूर्ण धार्मिक महोत्सव का मीडिया कवरेज पत्रकार जयराज बी. टांक (जयू) एवं भानुभाई पानशेरिया द्वारा किया गया।

नारी वंदन उत्सव-2026

सूरत में 181 अभयम की तीन टीमों द्वारा पांच स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

ब्यूरो रिपोर्ट - जे. बी. टांक,
पत्रकार, सूरत

राज्यभर में आयोजित 'नारी वंदन उत्सव-2026' के अंतर्गत 'महिला कर्मयोगी दिवस' के अवसर पर 181 अभयम महिला हेल्पलाइन की तीन टीमों द्वारा जिले के पांच विभिन्न स्थानों पर विद्यार्थियों एवं नागरिकों को महिला सुरक्षा, बाल अधिकारों तथा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।

पहले कार्यक्रम में बारडोली अभयम टीम ने वराड गांव स्थित श्री वल्लभ कन्या छात्रालय में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान काउंसलर तृप्तिबेन पटेल ने छात्राओं से संवाद कर 181 हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली तथा आपातकालीन परिस्थितियों में उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। साथ ही सभी छात्राओं को जानकारीपूर्ण पेम्फलेट भी वितरित किए गए।

दूसरे चरण में उमरा अभयम टीम ने पांडेसरा स्थित सुमन हाईस्कूल में विद्यार्थियों को महिला एवं बाल सुरक्षा, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम **(POSH)**, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 इमरजेंसी सेवा, वन स्टॉप सेंटर **(OSC)** तथा **PBSC** सेंटर से मिलने वाली सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का मार्गदर्शन काउंसलर निशाबेन ने किया।

इसी प्रकार कतारगाम अभयम टीम ने अमरोली स्थित संत श्री सवैयानाथ प्राथमिक विद्यालय, डॉ. राममनोहर लोहिया प्राथमिक विद्यालय तथा सिंगणपुर सुमन आवास में विभिन्न जागरूकता सेमिनार आयोजित किए। काउंसलर दक्षाबेन चौधरी ने 181 मोबाइल ऐप के उपयोग तथा महिला सुरक्षा से जुड़ी त्वरित सहायता सेवाओं की जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान काउंसलरों ने समाज से बाल विवाह, बाल मजदूरी और बाल शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने तथा साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों से अपील की कि किसी भी प्रकार की समस्या या आपात स्थिति में बिना किसी संकोच के 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 112 इमरजेंसी सेवा का उपयोग करें।

Printed / Published /Owned by ILEVAN H. THAKAR on behalf of ILEVAN H. THAKAR and Printed at JAY GRAPHICS AND PRINTERS, C/15, Vikram Chambers, Income Tax, Ashram Raod, Ahmedabad - 380 009.
Published at 1-503, Pramukh Aura, Nr. Pramukh Nagar Bunglows, Pramukh Nagar Road, Kh-0 Road, Sargasan Char Rasta, GANDHINAGAR.(GUI) Editor: ILEVAN H. THAKAR